RURAL DEVELOPMENT PROGRAMMES :-

स्वतन्त्रता-प्राप्ति के पश्चात 1 अप्रैल, 1951 से नियोजित आर्थिक विकास के माध्यम से ग्रामीण-विकास कार्यक्रमों पर बल दिया जा रहा है। भारत में सामाजिक न्याय के साथ प्रगति हो, यह लगभग सभी योजनाओं का मूल उद्देश्य रहा है।

ग्रामीण विकास की कुछ महत्वपूर्ण योजनाओं का संक्षिप्त विवरण निम्न प्रकार है :-

1. महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी अधिनियम (MNREGA) :- 1 अप्रैल, 2008 से इस योजना को पुरे देश में लागू कर दिया गया। इस योजना के तहत चयनित जिलों में ग्रामीण क्षेत्रों में प्रत्येक परिवार के एक लक्ष्य को वर्ष में कम से कम 100 दिन की अकुशल श्रमिक वाले रोजगार की गारण्टी दी जाती है।

2. स्वर्ण जयन्ती ग्राम स्वरोजगार योजना (SGSY) :- इस योजना की शुरुआत 1 अप्रैल 1999 ई० को हुआ। इस योजना के तहत गरीबी रेखा से नीचे के जिन परिवारों को शामिल किया जाता है उनमें 50 प्रतिशत अनुसूचित जाति/जनजाति, 40 प्रतिशत महिलाओं तथा 3 प्रतिशत विकलांगों के लिए आरक्षण है। योजना के कार्यान्वयन के लिए एक समिति द्वारा प्रतिवर्ष चयन का लक्ष्य तय किया जाता है। समिति में वित-

मंत्रालय, नाबार्ड, रिजर्व बैंक, एग्जिम बैंक तथा ग्रामीण विकास मंत्रालय के प्रतिनिधि होते हैं।

3. प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (PMGSY):- केंद्र सरकार द्वारा प्रायोजित प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना 25 दिसम्बर, 2000 को प्रारंभ की गई। इस योजना का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में सड़क विहीन गाँवों को बारहमासी सड़कों से इस प्रकार जोड़ना है कि सामान्य रूप से 500 से अधिक आबादी वाले गाँव व पहाड़ी जनजातियों एवं रेगिस्तानी क्षेत्रों में 250 से अधिक आबादी वाले गाँव आपस में जोड़े जा सकें।

4. इंदिरा आवास योजना (IAY):- आवास की बुनियादी आवश्यकता की पूर्ति के लिए वर्ष 1985-86 में इंदिरा आवास योजना को RLEGP की एक उप योजना के रूप में शुरू की गई थी। इस योजना का उद्देश्य अनुसूचित जाति, जनजाति तथा मुक्त बंधुआ मजदूरों को निःशुल्क आवास उपलब्ध कराना है। इस योजना का वित्त पोषण केंद्र और राज्यों के बीच 75:25 के अनुपात में किया जाता है।

Scanned with CamScanner

5. राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन (NRHM):-

इस कार्यक्रम की शुरुआत 12 अप्रैल, 2005 को ग्रामीण क्षेत्रों में निर्धनतम परिवारों को वहनीय और विश्वसनीय गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएँ उपलब्ध कराने हेतु की गई थी।

6. अन्नपूर्णा योजना:- निर्धनता रेखा से नीचे जीवन-यापन करने वाले लोगों की सहायता के लिए अन्नपूर्णा योजना। अप्रैल, 2000 से आरम्भ हुई।

7 राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना:- राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना के अन्तर्गत गरीबी रेखा से नीचे के वैसे परिवार को जिनके एक मात्र व्यक्ति कमाने वाला हो, उनकी सामान्य या दुर्घटना से मृत्यु होने पर रु० 10,000 दिये जाते है। मृत्यु के समय उनकी उम्र 18 वर्ष से 64 वर्ष के बीच होनी चाहिए।

8. ग्रामीण क्षेत्रों में शहरी सुविधाओं के प्रावधान की योजना:- 15 अगस्त 2003 से 'पुरा' योजना प्रायोगिक तौर पर सात राज्यों आन्ध्र प्रदेश, असोम, बिहार, महाराष्ट्र, उड़ीसा, राजस्थान तथा उत्तर-प्रदेश में शुरु की गई।

9 जवाहर रोजगार योजना:-

Scanned with CamScanner

जवाहर रोजगार योजना देश का सबसे बड़ा ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम है। इस योजना का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगार और अपर्याप्त रोजगार प्राप्त पुरुषों और महिलाओं के लिए अतिरिक्त लाभप्रद रोजगार का सृजन करना है। इसे केन्द्र और राज्यों द्वारा 80:20 के अनुपात में वित्त पोषित किया जाता है।

10, ग्रामीण रोजगार गारण्टी कार्यक्रम :-

2 फरवरी, 2006 से प्रारम्भ इस योजना के अन्तर्गत देश के 200 चयनित जिलों के ग्रामीण क्षेत्रों में प्रत्येक परिवार के एक वयस्क सदस्यों को वर्ष में न्यूनतम 100 दिन अकुशल काम वाले रोजगार प्राप्त करने का कानूनी अधिकार है।

The End

Thank you

Scanned with CamScanner